



## भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण योजनाओं का योगदान

1. आषीष कुमार धोटे 2. डॉ. रामसिंह कुषवाह 3. डॉ. प्रीति नायक 4. डॉ. श्वेता त्रिपाठी मध्यांचल प्रोफेशनल युनिवर्सिटी भोपाल

भारत ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण राष्ट्र रहा है, जिसकी दो तिहाई आबादी अभी भी वहां रहती है— यह देखते हुए कि, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसकी राष्ट्रीय आय का 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, और ग्रामीण विकास और विकास भारत के समग्र विकास और विकास का एक प्रमुख चालक है— इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी और शिक्षित ग्रामीण युवा अपने ज्ञान और कौशल से मेल खाने वाले रोजगार की तलाश करते हैं, जो एक आगामी सक्षम शक्ति रही है— इस प्रकार, भारत का भविष्य काफी हद तक ग्रामीण इलाकों के योगदान से आकार लेने वाला है— पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रगति के लिए ग्रामीण उपभोग आवश्यक रहा है, जिसे मुख्य रूप से बढ़ती डिस्पोजेबल आय द्वारा बढ़ावा मिला है— इसके अलावा जब कृषि और संबंधित ई-पोर्ट की बात आती है, भारत एक विश्व में अग्रणी है— पिछले कुछ वर्षों में, हमने पक्षी उद्योग, जलीय कृषि, मत्स्य पालन, और पशुपालन में वृद्धि देखी है— इसके अलावा, महामारी के प्रभावों में प्रति कृषि क्षेत्र के लचीलापन और भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ ग्रामीण भारत न केवल एक उल्लेखनीय निवेश विषय के रूप में उभरा है, बल्कि प्रमुख में से एक भी है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्तियाँ— उपरोक्त सभी कारण नए भारत के लिए आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को दोहराते हैं—

मुख्य शब्द: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, तथा भारत

### परिचय

भारतीय जनसंख्या का दो तिहाई हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, ग्रामीण भारत सच्चे भारत का वास्तविक चित्रण है— भारत का ग्रामीण इलाका विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, बोलियों, जातीयताओं, आदि का समामेलन है—जो दुनिया में भारत को एक अद्वितीय कद प्रदान करता है— यह देखते हुए कि, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसकी राष्ट्रीय आय का 50% से अधिक हिस्सा है, ग्रामीण विकास और विकास भारत के समग्र विकास और विकास के पीछे एक मुख्य चालक हैं— अध्ययनों से पता चला है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने समग्र अर्थव्यवस्था की मंदी के समय में भी देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगातार समर्थन और योगदान दिया है—भारतीय आर्थिक आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख स्थिति को समझना, यह सषक्त भारत के निर्माण में एक प्रमुख योगदानकर्ता होने जा रहा है—सषक्त भारत केवल एक सीमित मात्रात्मक विकास अवधारणा नहीं है, बल्कि गुणात्मक संकेतकों पर विस्तार और उत्थान के बारे में भी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों मोर्चों पर योगदान देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। उदाहरण के लिए ग्रामीण भारत ने हाल ही में महामारी के परिणाम स्वरूप मांग में बढ़ोतरी का नेतृत्व करने के लिए जीवन स्तर में सुधार और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना— फिर भी, आर्थिक नवाचार के लिए अभी भी कई अप्रयुक्त अवसर हैं— महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कई नीतियां, प्रोत्साहन, और पहल की हैं—

इसके अलावा, भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृषि से 1 ट्रिलियन डॉलर, सेवाओं से 3 ट्रिलियन डॉलर और विनिर्माण क्षेत्र से 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करने की उम्मीद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभ्य और उत्पादक नौकरियों के सृजन और सतत विकास और आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की महत्वपूर्ण क्षमता है। इसे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में आगे मान्यता दी गई है, जो विशेष रूप से ग्रामीण विकास और कृषि और खाद्य सुरक्षा की ओर ध्यान बढ़ाने के लिए तैयार है।

यह शोध पत्र नए भारत के निर्माण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। इसे दो भागों में लिया गया है। पहले भाग में, यह विश्लेषण करता है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने में कैसे एक मजबूत आधार रही है और दूसरे भाग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नए भारत के निर्माण में योगदान करने की क्षमता और संबंधित सरकारी पहलों को स्पष्ट किया गया है।

## शोध पद्धति

शोध पत्र एक ऐसा प्रयास है जो विश्वसनीय प्रकाशनों, इंटरनेट, लेखों, पाठ्यपुस्तकों और समाचार पत्रों से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा पर आधारित है। अध्ययन का शोध डिजाइन मुख्य रूप से वर्णनात्मक प्रकृति का है।

## साहित्य समीक्षा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्ता को इस तथ्य से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारतीय जनसंख्या का बढ़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23) पर निर्भर है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा उत्पन्न करती है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दो तिहाई से अधिक रोजगार उत्पन्न होता है (नीति आयोग, 2017)।

आयोग ने इस निष्कर्ष पर भी प्रकाश डाला है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में जोड़े गए मूल्य का आधे से अधिक योगदान ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों में जोरदार वृद्धि का अनुभव किया, जो देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 19.4% (2022–23) का बढ़ा योगदान देता है, जो 2021–22 में 18.8% और 2020–21 में 3.6% की वृद्धि दर्ज करता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23)। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्र लगातार उच्च विकास वाले क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक बनकर उभर रहे हैं (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23)। भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास काफी हद तक कृषि पर निर्भर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक प्रणाली में पूरे जोश के साथ भाग लेने के लिए तैयार किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी (पीएचडी रिसर्च ब्यूरो, 2018)।

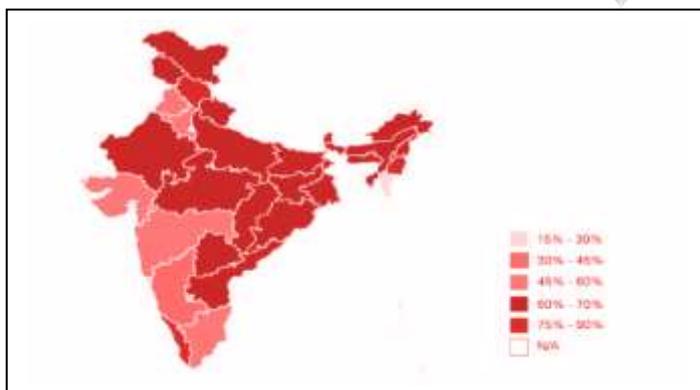
भारतीय खाद्य और कृषि परिषद (ICFA), 2018, जिसने आजादी से शुरू होकर पिछले 70 वर्षों के दौरान कृषि और भारतीय किसानों की प्रगति का अध्ययन किया, कृषि में उत्पन्न रोजगार के स्तर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि की भूमिका पर प्रकाश डालता है। 2014 की एसएस रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएस), 2022 में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियां 29.8% बढ़ी हैं।

## निष्कर्ष

### 1. महामारी के बाद रिकवरी की मजबूती

लगभग पिछले दो दशकों से भारत की ग्रामीण प्रति व्यक्ति जीडीपी लगातार 6.2% की दर से बढ़ी है। ग्रामीण भारत की वृद्धि, आय और उपभोग पैटर्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी रहती है। इनमें मांग को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने की क्षमता है। इसके अलावा, इस तर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तथ्य हैं कि समग्र अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लचीली रही। (कोविड-19 महामारी के कारण, वित्त वर्ष 2020–21 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो पिछले 15 वर्षों में दर्ज की गई सबसे खराब गिरावट है, जब से देश ने तिमाही आधार पर जीडीपी आँकड़े संकलित करना शुरू किया है।)

## ग्रामीण भारतीय जनसंख्या



पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रगति के लिए ग्रामीण खपत आवश्यक रही है, जिसे मुख्य रूप से बढ़ती डिस्पोजेबल आय से बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, जब कृषि से संबंधित निर्यात की बात आती है, तो भारत एक विश्व अग्रणी है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने पक्षी उद्योग, जलीय कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन में वृद्धि देखी है। इसके अलावा, महामारी के प्रभावों के लिए कृषि क्षेत्र की लचीलापन और भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देने के साथ, ग्रामीण

भारत न केवल एक उल्लेखनीय निवेश विषय के रूप में उभरा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्तियों में से एक भी है।

हालांकि, COVID 19 महामारी के दौरान, केवल कृषि क्षेत्र में वृद्धि (3.4% वृद्धि) देखी गई, जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे कुल दर नकारात्मक 28% हो गई।

वित्त वर्ष 2022 में मानसून सीजन (पिछले छह वर्षों में दर्ज उच्चतम स्तर), सिंचाई जलाशयों में पानी की प्रचुरता, खरीफ सीजन के लिए बोई गई फसलों द्वारा कवर किया गया अधिक क्षेत्र और अन्य सरकारी कल्याणकारी हस्तक्षेपों के साथ-साथ एमजीएनआरईजीएस का सफल कार्यान्वयन। खुदरा, रियल एस्टेट, परिवहन, निर्माण और विनिर्माण जैसे श्रम-गहन क्षेत्र COVID-19 लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं और उसने लचीलापन दिखाया।

व्यावसायिक दृष्टिकोण से, ग्रामीण खपत में वृद्धि द्वारा समर्थित भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लचीलापन ने ग्रामीण भारत को एक संभावित निवेश विषय के रूप में स्थापित किया है।

इसके अलावा, प्राथमिक रिपोर्टों और संकेतकों के आधार पर, आर्थिक रुझान बताते हैं कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत पैटर्न भारत की आर्थिक सुधार में एक मार्गदर्शक शक्ति होगी।

## 2. सशक्त भारत के निर्माण और सरकारी पहल में योगदान देने की संभावना

भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बाजार तेजी से शक्तिशाली आर्थिक चालक बन रहे हैं। कई नीति निर्माता और व्यवसाय इन बाजारों द्वारा प्रस्तुत घातीय वृद्धि की संभावनाओं से उत्साहित हैं। उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यवसाय बनने की चाह रखने वाली कंपनियाँ भारत के ग्रामीण बाजारों की क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। ऐसे आशाजनक आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ग्रामीण बाजार मुख्य रूप से उपभोक्ता की बढ़ती क्रय शक्ति से प्रेरित हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए एक प्रमुख चालक है।

### संभावनाओं का आकलन

केवल वर्तमान परिदृश्यों से नहीं किया जा सकता है। इस विशेष संदर्भ में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल बहुत आगे है, बल्कि यह उन मजबूत स्तंभों में से एक रही है जिसका आकलन दिए गए आंकड़ों से किया जा सकता है।

### तालिका क्रमांक-1

विवरण	अर्थव्यवस्था	कामगार
2001-02	86.69%	69%
2005-06	45%	80%
2010-11	60.5%	81.5%
2015-16	69.3%	86%
2020-21	46.3%	89.4%
2024-25	54.5%	89.6%

### एनडीपी और कार्यबल में ग्रामीण पृष्ठभूमि का हिस्सा

तालिका 1 में 2001 के दशक से 2024 के दशक तक एनडीपी और कार्यबल में ग्रामीण पृष्ठभूमि की हिस्सेदारी को दर्शाया गया है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे दशकों से शहरी केंद्रों के योगदान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया है, फिर भी अधिकांश (89.6%) आबादी ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है।

- कृषि विकास दर और जीडीपी विकास दर

स्रोत: पीएचडी रिसर्च ब्यूरो, 2018

तालिका क्रमांक-2

वर्ष	कृषि विकास दर	GDP विकास दर
2001-02	6%	6%
2005-06	5.8%	9%
2010-11	-04%	30.4%
2015-16	-02%	7.6%
2020-21	2.81%	7.25%
2024-25	1.4%	6.14%

तालिका 2 में दिए गए वर्षों में कृषि विकास दर और जीडीपी विकास दर के बीच संबंध दर्शाया गया है। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है, जीडीपी विकास दर और कृषि विकास दर के बीच सकारात्मक संबंध रहा है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृषि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह यह भी दर्शाता है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोजगार, वृद्धि और विकास का एक अप्रयुक्त स्रोत है क्योंकि ग्रामीण भारत वर्तमान में आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की पुनर्जीवित भावना से प्रेरित हो रहा है।

- भारत के विदेशी व्यापार में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा:

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, 2017-18 में भारत के निर्यात में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी 12.7: थी, 2018-19 में 11.8: थी और 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) में यह घटकर 10.6: रह गई। दूसरी ओर, भारत के आयात में खाद्य और संबद्ध उत्पादों का आयात क्रमशः 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में 4.4:, 3.2: और 3.3: रहा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत के विदेशी व्यापार में कृषि क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है। भारत की कुल अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका को देखते हुए, इस बात की काफी गुंजाइश और उम्मीद है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी। रोजगार, जीडीपी विकास दर, राष्ट्रीय आय और भारत के विदेशी व्यापार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नए भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, भविष्य में आगे बढ़ने के साथ-साथ भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है, जैसा कि



चित्र 2 में दिखाया गया है। इसलिए, भारत सरकार ने वर्तमान आर्थिक गतिशीलता में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्षमता के क्षेत्रों पर बहुत जोर दिया है। ये क्षेत्र कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और एफएमसीजी हैं।

**चित्र 2 :** सरकार ने निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए दूरदर्शी नीतियों और हस्तक्षेपों का सुझाव दिया है, जिसका ध्यान उपर्युक्त क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर है।

कोविड-19 के कारण, भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में ढह रही है, जिससे नुकसान को सीमित करने और लोगों को अपना रोजगार बनाए रखने की अनुमति देते हुए अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इनमें से अधिकांश हस्तक्षेप केंद्रीय बैंक की आपातकालीन तरलता पर केंद्रित एक व्यापक आर्थिक उपाय प्रदान करते हैं।

इनमें सामान्य कर राहत, वेतन/आय सब्सिडी, बेरोजगारी बीमा, भुगतान स्थगित करने की क्षमता और खराब प्रदर्शन करने वाले व्यवसायों में सरकारी इक्विटी निवेश जैसी राजकोषीय नीतियां भी शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे संबंधित क्षेत्रों में उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई कुछ सरकारी पहल यहां दी गई हैं।

 <p>Agriculture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृषि निर्यात नीति कृषि</li> <li>• 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना</li> <li>• न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि</li> <li>• छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम पेंशन</li> <li>• पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत शून्य लागत पर खाद्यान्न</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य 2022 तक निर्यात को दोगुना करना और अगले कुछ वर्षों में 24 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचना है</li> <li>• पीएम गरीब कल्याण योजना (आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा) का उद्देश्य प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है</li> </ul>
 <p>उपभोग्य FMC&amp;G</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सिंगल और मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए एफडीआई में छूट</li> <li>• जीएसटीआई के कारण लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सुविधाओं में बदलाव</li> <li>• 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट</li> <li>• पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एक पायलट के तौर पर, सरकार अपने डिजिटल विनिर्माण कार्यक्रम के माध्यम से 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करने का इरादा रखती है</li> <li>• पीएम ग्राम सड़क योजना असंबद्ध गांवों को हर मौसम में अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है</li> </ul>
 <p>स्थायी उपभोक्ता</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एकल और बहु ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के लिए एफडीआई छूट</li> <li>• संशोधित प्रोत्साहन स्थानीय स्तर पर विनिर्माण करते हैं</li> <li>• ग्रामीण क्षेत्रों को निवेश स्थलों के रूप में बढ़ावा देते हैं</li> <li>• नीतियों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहित करते हैं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने वाले प्रोत्साहनों को बढ़ावा देती है</li> <li>• "भारत में मकान" कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है।</li> </ul>
 <p>बैंकिंग Banking</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रामीण क्षेत्रों को निवेश स्थलों के रूप में बढ़ावा देते हैं</li> <li>• किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना</li> <li>• स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना</li> <li>• जन धन योजना के माध्यम से ग्रामीण वित्तीय समावेशन</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीएम जन धन योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच का विस्तार करना है</li> <li>• किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य किसानों को कृषि आवश्यकताओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करना है</li> </ul>
 <p>ग्रामीण विकास Rural development initiatives</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एमजीएनआरईजीएस को लागू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 40,000 करोड़ रुपये</li> <li>• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (आईडीडीयू-जीकेवाई) के तहत ग्रामीण और कौशल पहल</li> <li>• 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MGNREGS काम के अधिकार की गारंटी देता है</li> <li>• DOU&amp;GKY का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है</li> <li>• प्रवासी श्रमिकों पर COVID के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया</li> </ul>

## सरकारी हस्तक्षेप

### ग्रंथ सूची

1 दास, ए., राजा, आर., और पटनायक, एन.एम. (2020)। भारत की ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति, प्रभाव और निर्धारण कारक एक समीक्षा। भारतीय अर्थशास्त्र और विकास जर्नल, 16(28), 68-76।

2. राहुल कुमार, एमएस अब्दीन (2020) भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर रही हैरू योगदान अवसर और चुनौतियाँ, 1009–1018।
3. सुमंत भट्टाचार्य (2022) भारत के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, 101–106–आर्थिक सर्वेक्षण (2021–2022)। कृषि और खाद्य प्रबंधन, 235–260
5. नीति आयोग (2017)। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना का रोजगार और विकास पर प्रभाव
6. ग्रामोदय का समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान हुआ है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है। (2020, अगस्त) फाइनैशियल एक्सप्रेस
7. केपीएमजी और भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्टरू भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्थारू आर्थिक पुनरुद्धार और सतत और न्यायसंगत विकास की कुंजी (2020)

